मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता। दुनिया के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है। दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा।

RN 42233

नई सीरीज नम्बर 7 जनवरी 1989 50 पैसे

पूँजी के नुमाइन्दों के बदलते चेहरे

पूंजी एक सामाजिक सम्बन्ध है। मजदूर लगा कर मंडी के लिये प्रोडक्शन इस सामाजिक सम्बन्ध का निचोड़ है। पूंजी के नुमाइन्दों का काम होता है मजदूरों को कम से कम पैसे देकर उनसे अधिक से अधिक काम करवाना। मजदूरों को हाड़-माँस की मशीन बनाने का काम करने के बदले में पूँजी के नुमाइन्दों को कोठी-कार-नौकर-चाकर जैसी सुविधायें मिलती हैं।

बीते समय के मेहनतकशों का खून-पसीना ही पूंजी के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर कब्जा किसी एक का है, या कुछ लोगों का है, या "सब" का है। कारखाना चाहे किसी पूँजीपति का हो, चाहे कुछ पूंजीपतियों का प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे कई शेयर होल्डरों का लिमिटेड हो, और चाहे "सार्वजनिक क्षेत्र का" उर्फ सरकारी कारखाना ही क्यों न हो—जब तक मजदूर लगाकर मंडी के लिये प्रोडक्शन है तब तक मजदूरों का दमन-शोषण है।

पूंजी वाला सामाजिक सम्बन्ध सदा से नहीं है। एक ताकत के तौर पर यह सम्बन्ध आज से दो-ढाई सौ साल पहले शुरू हुआ। पूंजी के नुमाइन्दे पहले-पहल पूंजीपति के रूप में उभरे। उस समय "यह कारखाना फलाने का है" जैसी बात थी क्योंकि ज्यादातर कारखाने इस या उस व्यक्ति ने "निजी" पैसे से लगाये थे। तब आमतौर पर कारखाने का मालिक हर रोज मजदूरों के सिर पर खड़ा रहता था। मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिये वह हर हथकण्डा अपनाता था। हर मालिक की कोशिश होती थी कि वह अधिक से अधिक मुनाफा वसूले।

तेजी से बन रही नई-नई और भारी-भरकम मशीनों ने जल्दी ही कारखाने की इतनी बड़ी साइज जरूरी बना दी कि ऐसे कारखाने लगाना एक या दो पैसेवालों के बलबूते से बाहर की चीज हो गई। प्रोडक्शन की ताकतें इतनी बढ़ गई कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिये कई पैसेवालों द्वारा मिलकर काम करना जरूरी हो गया—जोइन्ट स्टाक कम्पनियों, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कम्पनियों की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण-सरकारीकरण की भी जड़ में यही बात है। पूंजी के नुमाइन्दों ने मालिकों की जगह डाइरेक्टरों का रूप ग्रहण किया। आज आमतौर पर पूंजी के नुमाइन्दे मैनेजमेंटों के रूप में हैं।

मैनेजमेंट चाहे प्राइवेट लिमिटेड की हो, लिमिटेड की हो, चाहे सरकारी कम्पनी की ही क्यों न हो— सब मैनेजमेंटों का काम है कम से कम पैसों में मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम करवाना। मैनेजमेंट में इस आदमी की जगह उस आदमी को रखने और इस नीति की जगह उस पालिसी को अपनाने से मैनेजमेंट के काम की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात के हिसाब से साम-दाम-दंड-भेद में परिवर्तन करना मैनेजमेंट की सामान्य राह है।

भारत में पूंजी कमजोर है। इसलिये आज भी पूँजी के हर तरह के नुमाइन्दे यहाँ मौजूद हैं। वर्कशापों आदि में दो-चार-दस मजदूर रखने वाले मालिक हैं; प्राइवेट लिमिटेड में परिवारजन-मित्र डाइरेक्टर हैं; लिमिटेड में फलां की मैनेजमेंट में कई तरह के डाइरेक्टर हैं; सरकारी कम्पनियों में अफसर डाइरेक्टरों की मैनेजमेंटें हैं। पूंजी के नुमाइन्दों के इतने रूप तो कारखानों के दायरे में ही हैं। फिर भी, एक चीज यहाँ साफ-साफ दीखने लगी है—आमतौर पर वर्कशापों में भी पैसे बैंकों से लिये कर्ज के लगने लगे हैं। "अपने धन" से होने वाले धन्धे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में "अपने पैसे लगाये हैं तो मुनाफा क्यों नहीं लेंगे" वाली पुरानी पूंजीवादी दलीलें थोथी हो गई हैं। भारत में भी "अपने" पैसों पर नहीं बल्कि "सबके" पैसों पर मौज-मस्ती करने वाले पूंजी के नुमाइन्दों की भरमार है। ऐसे में हेरा-फेरी करना मैनेजमेंटों में शामिल लोगों का सामान्य चरित्र है। इसलिये प्राइवेट लिमिटेड-लिमिटेड-सरकारी कम्पनियों में अधिकारियों का भ्रष्टाचार आम चीज है। और यह चीज भारत में पूंजी के नुमाइन्दों की ही खासियत नहीं है। अमरीका जैसे शक्तिशाली पूंजी के इलाकों में भी पूंजी के नुमाइन्दों का भ्रष्ट आचरण सामान्य बात है। और तो और, पूंजी के पूर्ण सरकारीकरण वाले रूस में भी पूंजी के नुमाइन्दों का भ्रष्ट आचरण आम बात है—हाल ही में दिवंगत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के दामाद यूरी चुखानोव को करोड़ों की हेरा-फेरी के लिये जेल की सजा सुनाई गई है (श्री चुखानोव रूस में मन्त्री भी थे)।

मानव जीवन के लिये जरूरी चीजों का प्रोडक्शन किस ढंग से होगा, यह प्रोडक्शन की उन ताकतों पर निर्भर है जो मानवों द्वारा हासिल की जा चुकी हैं। प्रोडक्शन की ताकतों के एक खास स्तर, भाप-कोयला-मशीन ने पूंजीवादी ढंग के प्रोडक्शन को जन्म दिया। प्रोडक्शन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों ने पूंजी के नुमाइन्दों के रूपों को भी बदला है। आज रोटी-कपड़ा-मकान आदि की जरूरतें पूरी करने वाली प्रोडक्शन की मशीनरी इतनी डेवलेप हो गई है कि इसे मानव हित में दुनिया के आधार पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिये दुनिया के मजदूरों की एकता और पूंजी के नुमाइन्दों के सब स्वरूपों के खिलाफ मजदूरों द्वारा संघर्ष करने जरूरी हैं। पूँजीवाद को दफनाने पर ही मजदूरों को दमन-शोषण से मुक्ती मिलेगी।

दुनिया में मजदूरों के संघर्ष

"दुनिया के भूखो, एक हो !" पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने 1988 में यह नारा लगाया। पादरियों और उनसे जुड़े सरकार-विरोधी लीडरों ने "पोलैंड बचाओ !" का शोर मचाकर मजदूर पक्ष की उभरती आवाज को इस बार भी दबा दिया।

1980 में पोलैंड के मजदूरों ने खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ जबरदस्त हड़तालें की थी। हड़तालों की लहर ने बगावत की शक्ल ले ली थी और तब मजदूरों को दबाने के लिये पोलैंड में फौजी शासन लागू किया गया था। अपने को समाजवादी कहने वाले, पर असल में राज्य-पूंजीवादी देशों के पूंजी के नुमाइन्दों को पोलैंड में मजदूरों के उन संघर्षों ने काफी हद तक नंगा किया था।

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के गहरे होते संकट ने 1988 में पोलैंड में एक बार फिर 1980 की ही तरह हालात गम्भीर बनाये। पूंजी के नुमाइन्दों द्वारा अन्य देशों में उठाये जा रहे कदमों की तरह के ही कदम पोलैंड में भी उठाये गये। फरवरी 1988 में 'आर्थिक सुधार योजना' के नाम पर पोलैंड की सरकार ने आम जरूरत की चीजों के भाव औसतन 45 प्रतिशत बढ़ाये। मजदूरों को पुचकारने के लिये सरकार ने वादा किया कि बढ़े भावों को बेअसर करने के लिए मजदूरों को बोनस दिये जायेंगे। पर वास्तव में दुनिया-भर में भाव बढ़ाये ही इसलिये जाते हैं कि मजदूरों की असल तनखा कम करके पूंजीवादी संकट से पूंजी के नुमाइन्दों को कुछ राहत मिले। इसलिये जल्दी ही पोलैंड सरकार की पोल खुल गई। मार्च के आरम्भ में पोलैंड में जगह-जगह मजदूरों ने मीटिंगें कीं और कम बोनस दिये जाने के खिलाफ हड़ताल की धमकियां दीं। 4 मार्च को रोकलों में बस रिपेयर डिपो पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया जिस पर मैनेजमेंट ने मजदूरों की शर्तें मान ली। 9 मार्च को नाममात्र की कम्युनिस्ट, पोलैंड की शासक पार्टी ने अपने अखबार में मैनेजमेंट को मजदूरों के सामने झुकने के लिये लताड़ा। पर इस लताड़ने के बावजूद यह सिलसिला बढ़ता गया। 22 अप्रैल को स्टैलोवा में 5000 स्टील मजदूरों ने विरोध जलूस निकाला और तनखा न बढ़ाने की सूरत में हड़ताल की धमकी दी। 25 अप्रैल को बिगोजज शहर की नगर बस सेवा के मजदूरों ने चाणचक्क हड़ताल कर दी और 63 प्रतिशत वेतन बढ़ाने की माँग की। निकट के शहर इनोरोकलों के बस वर्कर भी हड़ताल में शामिल हो गये। 26 अप्रैल को नोवा हुटा के विशाल स्टील कारखाने के मजदूरों ने 50 प्रतिशत वेतन बढ़ाने, दुगने बोनस और 1981 में निकाले मजदूरों को वापस काम पर लेने के लिये हड़ताल कर दीं। 29 अप्रैल को हड़ताल स्टैलोवा वोला के भारी मशीनरी और हथियार निर्माण कारखाने तथा बोशनिया के स्टील कारखाने में फैल गई। मैनेजमेंट ने स्टैलोवा वोला में तालाबन्दी की कोशिश की पर मजदूरों ने कारखाने पर कब्जा कर लिया। इस पर हथियारबन्द पुलिस ने कारखाने को घेर लिया और मैनेजमेंट ने टेलिविजन पर मजदूरों को छँटनी की धमकी दी। और उधर सरकार ने नोवा हुटा की हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। 30 अप्रैल को स्टैलोवा मैनेजमेंट ने मजदूरों की वेतन बढ़ाने और निकाले हुये मजदूरों को काम पर लेने की माँगें मान ली। मई दिवस पर पोलैंड के 15 शहरों में मजदूरों की माँगों के समर्थन में जलूस निकाले गये। झगड़े हुये और वारशाव शहर में ही सैंकड़ों गिरफ्तार किये गये। 2 मई को गदान्सक शिपयार्ड के मजदूर हड़ताल में शामिल हो गये। 50 से 60 प्रतिशत वेतन वृद्धि, राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि माँगों के साथ उन्होंने शिपयार्ड पर कब्जा कर लिया और एक स्ट्राइक कमेटी चुनी। रोकलों के पास डोलमेल प्लान्ट में भी हड़ताल हुई जिस पर मैनेजमेंट ने वेतन बढ़ाने की माँग मान ली। 4 मई को लुबिन

हमारे लक्ष्य हैं— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुँचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिये जरूरी दुनिया के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बँटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को तालमेल के लिये हमारा खुला निमंत्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका-टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

सम्पर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन० आई० टी० फरीदाबाद—121001

हम जातिवाद, भाषावाद, इलाकावाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और धर्म के नशे के खिलाफ हैं।

के कोयला खदान मजदूर और पोकोनिस की ताम्बा खान के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 5 मई को सुबह के दो बजे पुलिस ने हमला बोलकर नोवा हुटा स्टील प्लान्ट से हड़तालियों को खदेड़ दिया। इसमें 32 मजदूरों को चोटें आईं और 32 गिरफ्तार किये गये। पुलिस हमले की खबर फैलते ही ज़ज़न और पोलिस में ट्रान्सपोर्ट वर्करों और गिनिआ के शिपयार्ड मजदूरों ने काम छोड़ दिया और विरोध जलूस निकाले। 6 मई को नोवा हुटा के 32,000 में से 10,000 मजदूर फिर भी हड़ताल पर रहे। गदान्सक शिपयार्ड पर पुलिस ने घेरा कस दिया—टेलीफोन लाइनें काट दीं और मजदूरों के लिये भोजन पर रोक लगा दी। 7 मई को मैनेजमेंट ने 40 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव किया पर मजदूरों ने उसे ठुकरा दिया। 10 मई को हड़तालों का यह दौर खत्म हुआ। (इंटरनैशनलिस्ट पर्सपैक्टिव पत्रिका, अंक 11 से सामग्री ली है।)

अपने साथी मजदूरों के वीरतापूर्ण संघर्षों से उत्साहित होने के साथ-साथ हमें उन संघर्षों में उभरी कमजोरियों को भी समझना चाहिये। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कदम उठाकर ही मजदूर वर्ग का संघर्ष आगे बढ़ सकता है।

पोलैंड के इन मजदूर संघर्षों में भी यह तथ्य सामने आया कि पूँजीवादी पक्ष और मजदूर पक्ष में मजदूर फर्क नहीं कर पाये। पादरियों और उनसे जुड़े लीडरों का पोलैंड के मजदूरों में इस समय काफी प्रभाव है। दुनिया-भर में आज शासक पूंजीवादी गुटों के खिलाफ असन्तोष का लाभ विरोधी पूंजीवादी गुट ही ज्यादातर उठा रहे हैं। वी० पी० सिंह और राजीव गाँधी के गिरोहों में क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है फिर भी राजीव सरकार के खिलाफ गुस्से को भुनाने में वी० पी० सिंह जैसे लोग सफल होते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का मूल कारण मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन में आई उलझनें हैं। इस वजह से एक तरह के पूंजी के नुमाइन्दे सोशलिस्ट-कम्युनिस्ट के बिल्ले लगाकर मजदूरों को पूंजीवादी दलदल में फँसाते हैं तो दूसरी तरह के पूंजी के नुमाइन्दे, मुल्ले-पादरी-पुजारी मजदूरों के उद्धारक बनकर उन्हें धार्मिक अफीम की घुट्टियां पिलाते हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिये मजदूर वर्ग के सिद्धान्त को पैना करना जरूरी है। मौजूदा हकीकत को समझने और इसे बदलने के लिये मार्क्सवाद का विकास करना जरूरी है। पैने क्रान्तिकारी सिद्धान्त के आधार पर ही शक्तिशाली क्रान्तिकारी मजदूर संगठन बन सकेगा, तभी मजदूर पक्ष तेजी से आगे बढ़ेगा।

जूट मिल के मजदूरों का रोना

छोटेलाल आजकल रिक्शा चलाते हैं। 1974 में वे ईस्ट इंडिया काटन की जूट मिल में भरती हुये थे। 1983 में अचानक जूट मिल में ताला लगने के बाद से छोटेलाल अपनी सर्विस, बकाया वेतन और फन्ड के पैसों की आस में फरीदाबाद में हैं—यहाँ टिके रहने के लिये वे रिक्शा चला रहे हैं। पाँच साल से ऊपर हो गये हैं पर उन पैसों का कोई सिर-पैर तक छोटेलाल को नजर नहीं आया है। जूट मिल के ही 900 और छोटेलाल हैं जिनमें से 2-3 सौ ही इस समय फरीदाबाद में झख मार रहे हैं—बाकी यह भी नहीं कर पाये, वे इधर-उधर बिखर गये हैं। फरीदाबाद में ही जूट मिल की तरह कई फैक्ट्रियाँ बन्द हैं। इनके हजारों छोटे लालों को भी वह पैसा नहीं मिला है जो पूंजीवादी कानूनों के मुताबिक उनका बनता है। वास्तव में, पूंजीवादी कानून मजदूरों को उल्लू बनाने के लिये हैं।

जूट मिल, पावरलूम, डावर, अजन्ता आदि मिलकर ईस्ट इंडिया काटन कम्पनी कहलाती थी। जूट मिल को छोड़कर बाकी को आज भी ईस्ट इंडिया में गिना जाता है। जूट मिल मजदूरों के पैसों का जब सवाल उठा तब ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट ने उन मजदूरों को अपना मानने से ही इन्कार कर दिया और कहा कि वे तो फाइबर प्रौसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के मजदूर हैं। ईस्ट इंडिया के मजदूर जान लें कि फिर कभी मौका पड़ने पर वैसा ही करने के लिये ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट ने कम्पनी के अन्दर कई और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ बना रखी हैं। फरीदाबाद में ही कई अन्य फैक्ट्रियों में भी ऐसा है। एक मैनेजमेंट द्वारा एक फैक्ट्री के गेट के अन्दर कई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के बोर्ड लगाने के पीछे छिपी चाल मजदूरों को तब पता चलती है जब कानूनी पचड़ों में मैनेजमेंट के वकील ऐसे रजिस्ट्रेशनों के आधार पर बक-बक करने लगते हैं और मजदूरों से कहा जाता है कि जिस मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने केस किया है उसके तो वे वर्कर ही नहीं हैं।

सितम्बर 1983 में कच्चे माल की कमी के नाम पर जूट मिल में एक महीने का ले-आफ किया गया। उस समय मजदूरों की दो महीनों की तनखा बकाया थी—हर मजदूर को 200 रुपये दिये गये और उन्हें यह कहकर घर घूम आने को कहा गया कि तब तक जूट आ जायेगा। और अक्टूबर में जूट मिल का कोई जवाबदेह ही नहीं बना—ताला बेशक ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट ने ही लगाया और उसी ने अपनी सैक्यूरिटी वाले वहाँ बैठाये। असल में ईस्ट इंडिया की लोहिया मैनेजमेंट और कटलर हैमर की भरतिया मैनेजमेंट में जूट मिल पर कब्जे के लिये खींचा-तान चल रही थी। मुकदमेबाजी के एक खास मोड़ पर पहुँच जाने पर वहाँ ताला लगाया गया।

कुछ बिचौलियों के जरिये 1983 में ही जूट मिल के मजदूरों ने केस किया था पर मजदूरों को मिला कुछ नहीं—चन्दा तो बिचौलियों की जेबों में गया ही, और क्या कुछ उनके पेट में गया इसकी पक्की जानकारी नहीं है। उधर बैंकों ने अपने पैसे वसूलने के लिये केस किया और उनके पैसों के लिये मई 1986 में जूट मिल की मशीनें नीलाम हो गई। फैक्ट्री में से मशीनें निकालने के समय मजदूरों में हलचल हुई। नये बिचौलिये आगे आये। फरीदाबाद में घिसट-पिसट कर टिके हुये जूट मिल के हर मजदूर से नये बिचौलियों ने 50 से 100 रुपये तक चन्दा लिया और केस कर दिया। तब फैक्ट्री से मशीनें नहीं निकली और बड़बोलों ने खूब लच्छेदार बातें की। लेकिन दिसम्बर 1988 में जब सब मशीनें फैक्ट्री से निकाल कर ले जाई गई तब वे बिचौलिये जूट मिल के गेट के आस-पास तक नजर नहीं आये—शायद घरों में ही भेंट-पूजा चढ़ा दी गई थी।

ईस्ट इंडिया की जूट मिल के 900 मजदूरों को आज तक हिसाब नहीं मिला है। और जूट मिल की खाली हुई बिल्डिंगों में ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट द्वारा प्रिंटिंग टेबलें लगाने की चर्चा चल रही है।

जूट मिल के मजदूरों के दुख-दर्द से इतना तो सीखा ही जा सकता है कि मजदूरों को पूंजीवादी कानूनों के पचड़ों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिये। क्लोजर और तालाबन्दी के समय मजदूरों को बिचौलियों के कागजी घोड़ों के चक्कर में पड़कर अपनी ताकत बिखरने नहीं देनी चाहिये—फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिये अपने बाजुओं की ताकत का मजदूरों को इस्तेमाल करना चाहिये। रात-बे-रात धोखे से ताले लगा दिये गये हों तो मजदूरों को उन तालों को फौरन तोड़ देना चाहिये। सैक्यूरिटी वालों और पुलिस से हाथा-पाई से डरने का मतलब है जूट मिल के मजदूरों की तरह हलाल होना। हिम्मत से आगे बढ़ना मजदूरों के लिये जरूरी है—यही उन्हें क्रान्ति के रास्ते पर, मुक्ती की राह पर आगे बढ़ायेगा।

के०जी० खोसला कम्प्रेसर

काफी झगड़े-झंझटों के बाद मजदूरों के नाम पर मैनेजमेंट के साथ 22 नवम्बर 88 को तीन साल की एग्रीमेन्ट पर दस्तखत किये गये। जैसा कि आमतौर पर होता है, इस एग्रीमेन्ट को भी मजदूरों की शानदार जीत कहा गया और इसका प्रचार किया गया। लेकिन मजदूरों के नाम पर दस्तखत करने वालों ने दिसम्बर में कहा कि मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा किया है। इस पल्टा खाने की जड़ में के० जी० खोसला के मजदूरों को 40 लाख रुपयों से ज्यादा का नुकसान है जिसका कि मजदूरों को पता चलने लगा था। इन हालात में बाहरी बिचौलिये ने भाषण झाड़ा कि उसने एग्रीमेन्ट पर यह समझकर दस्तखत कर दिये थे कि फैक्ट्री वर्करों में से जो आगे हो रखे हैं उन्होंने एग्रीमेन्ट को पढ़ लिया होगा। और फैक्ट्री मजदूरों में से आगेवान बने लोग कहते हैं कि उन्होंने इसलिये दस्तखत कर दिये कि बाहर के लीडर साहब ने पहले दस्तखत कर दिये थे।

लगता है कि एग्रीमेन्ट के खिलाफ मजदूरों के असन्तोष को उभरते देखकर मैनेजमेंट और मजदूरों के नाम पर दस्तखत करने वालों को लगा कि वे मजदूरों से राजी-खुशी से वह समझौता लागू नहीं करवा सकेंगे। इस पर मैनेजमेंट ने एक चाल चली। लोकदल की एल० एम० एस०, जिससे के० जी० खोसला के मजदूर बिदके हुए हैं, उसे मैनेजमेंट ने घास डाली। एल० एम० एस० इधर-उधर से 50-60 वर्करों को इकट्ठा करके के० जी० खोसला के गेट पर आ धमकी। उधर दस्तखत करने वाले लीडर साहब ने मोर्चा बाँधा और जूतम-पजार हो गई—वैसे एल० एम० एस० और लीडर साहब दोनों ही जनता दल की जयजयकार करते हैं।

इस सब में मजदूरों के 40 लाख से ज्यादा रुपयों की बात आई-गई हो गई है। लगता है कि जिन्होंने मजदूरों को नुकसान पहुँचाया है उन्हीं के गीत कुछ और समय तक खुशफहमी में के० जी० खोसला के मजदूर गाते रहेंगे। इस समय मैनेजमेंट के दोनों हाथों में लड्डू हैं।

के० जी० खोसला कम्प्रेसर के मजदूरों के साथ घटी घटनायें भी यही सीख देती हैं कि बिचौलियों पर भरोसे की राह मजदूरों की बरबादी की राह है।

कमला सिनटैक्स

यहाँ 80 वर्कर कम्पनी के रोल पर हैं और 350 वर्कर ठेकेदारों के हैं। 4 सैक्टर की कमला सिनटैक्स के सब वर्करों में इस बात पर एकता थी कि सबसे पहला काम ठेकेदारों को भगाना है। गुन्डागर्दी करना सब जगह ठेकेदारों की सामान्य राह है, कमला में भी थी। और जगहों के मजदूरों की तरह ही कमला सिनटैक्स के वर्कर भी उन बिचौलियों को ढूँढ रहे थे जो उनकी समस्यायें हल कर दें। लोकदल की एल० एम० एस० में कमला के वर्करों को अपने मसीहा मिल गये लगे। फैक्ट्री गेट पर हरा झंडा लग गया। और जल्दी ही मजदूरों ने देखा कि ठेकेदारों को हटाने की बातें हवा हो रही हैं।

इस बीच लड़ाकू मजदूरों को नरम करने के लिए उन्हें पहले उकसाया गया, उनमें फूँक भरी गई और फिर मार-पीट तथा रोहतक जेल में कुछ दिन बन्द करवाया गया। मजदूरों को मैनेजमेंट की लाइन पर लाने की कोशिशें जारी हैं। बिचौलियों से चौकस रहकर ही मजदूर अपने हितों की देखभाल कर सकेंगे।

एक मजदूर का खत

ट्रेड यूनियन लीडर "हिन्दू" बन गए

अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के जन्मदाता डा० हेडगेवार की जन्म शताब्दी मनाई गई। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, जमायते इस्लामी, अकाली दल आदि संगठन हिन्दू, मस्लिम तथा सिख धर्म के कट्टर संगठन माने जाते है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक उन्माद फैलाने में ऐसे संगटन जी-तोड़ कोशिशें करने के लिये बदनाम हैं। आम जनता इन्हें घास नहीं डालती परन्तु कुछ व्यापारी, बड़े-बड़े अधिकारियों के 'सुपुत्र', दो नम्बर का धन्धा करने वाले लोग ऐसे संगठनों को फलने-फूलने में खूब मदद करते हैं। इन्हीं कुख्यात संगठनों के लोग आये दिन साम्प्रदायिक जहर फैला कर हिन्दू-मुस्लिम-सिख झगड़े कराते रहते हैं, तो कभी बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का मसला उठाकर तनाव फैला रहे हैं।

धर्म निरपेक्षता का दम भरने वाले लोग, सरकार व बुद्धिजीवी भी अप्रत्यक्ष तरीके से इन्हें शाबासी देते है।

ऐसे ही लोगों में अब लाल झँडा फहराने वाले लोग भी शामिल हो गये हैं। H. M. S. के फरीदाबाद के जाने-माने लीडरों ने भी आर० एस० एस० के द्वारा आयोजित जन्म शती समारोह में पूर्ण योगदान किया। वैसे, इन्कलाब के इन ठेकेदारों से मजदूर अवश्य पूछेगा कि ट्रेड यूनियनों में धर्म के इस्तेमाल का H.M.S. को क्यों शौक चर्राया है ? तथा, मजदूरों में धार्मिक जहर फैलाना क्या सरमायेदारों के हित में नहीं है ?

—सुरेन्द्रसिंह, बाटा फैक्ट्री, फरीदाबाद

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेंसी द्वारा, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110031 में मुद्रित।